International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 219-225

21वीं सदी के भारत में कौशल विकास : अवसर और चुनौतियाँ

डॉ. मुकेश कुमार मीना*
डॉ. अखलेश कुमार मीना**

सार

प्रस्तुत शोध पत्र 21 वीं सदी के भारत में कौशल विकास के अवसर और चुनौतियों का वर्णन करता है। भारत में कौशल विकास की योजनाओं, नीतियों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केन्द्र में भारत की युवा आबादी और कौशल विकास को रखा गया है। कौशल विकास के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि, आत्मविश्वास तथा रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि होती है। वर्तमान में भारत वैश्विक माँग तथा अपनी विशाल आबादी के दम पर वैश्विक क्षमता केन्द्रो का हब बनता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह इन केन्द्रों को प्रोत्साहन दे ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकें।

शब्दकोशः *कौशल विकास, अवसर, चुनौतियाँ, रोजगार सृजन, सूचना प्रौधोगिकी कंम्पनियाँ।*

प्रस्तावना

प्राचीन काल में 'सोने की चिडिया' के नाम से प्रसिद्ध व समृद्ध भारत 21 वी सदी में फिर से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज संपूर्ण विश्व में भारत न केवल सामाजिक राजनैतिक बल्कि आर्थिक और वैज्ञानिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ एक विकासशील देश हैं। इस सदी में विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी, अन्तरिक्ष, चिकित्सा व स्वास्थ्य, योग व और खेल सभी क्षेत्रों में भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

आज भारतीय सॉफ्टवेयर एंव सूचना प्रौधोगिकी कंम्पनियाँ वैश्विक स्तर पर नित नये कीर्तिमान बना रही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बढोतरी के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि हुई है। निरन्तर प्रगति के कारण ही समूचे विश्व की नजरें 21 वीं सदी के भारत पर टिकी हुई है।

दुनिया विशेषकर विकसित देशों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदोलत आबादी लम्बी उम्र तक जी रही है। और उसकी उम्र बढती जा रही है। इस पैमाने पर जन सांख्यिकी बदलावों को अपनाने के साथ ही उसके लिए भावी योजना बनाना इस सदी की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों में से एक है। आज भारत अपनी 144 करोड अनुमानित आबादी के साथ इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड पर खड़ा है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है जो हमें एक युवा देश बनाता है। इसका एक फायदा यह है कि हम इन युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल मुहैया करा कर देश की न केवल उत्पादकता बढ़ा सकते है। बल्कि वैश्विक जरूरतों को भी पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते है।

---

* सहायक आचार्य, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू युनिर्वसिटी कालेज ऑफ टीचर ऐजूकेशन, आसनसोल, पश्चिम बंगाल।
** सहायक आचार्य, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू युनिर्वसिटी कालेज ऑफ टीचर ऐजूकेशन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

भारत में गुणवत्ता पूर्ण कौशल विकास के काम को इसलिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दक्षिण कोरिया, चीन, जापान इत्यादि के साथ यूरोपीय देशों में युवा आबादी तेजी से घट रही है और इन सभी देशों को विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद व कुशल युवाओं की तलाश है। भारत इस अवसर का लाभ उठाने में तभी सफल हो सकेगा, जब वह अपनी युवा आबादी को आज की तकनीकी, भविष्योन्मुखी कौशलो और तेजी से बदलते युग की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने में सक्षम होगा। यदि ऐसा किया जा सके तो भारत विश्व में कुशल जनशक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र बन सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- देश की युवा आबादी को बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना ।
- देश में बेहतर रोजगार और उत्पादकता के लिए कौशल विकास को बढ़ाना तथा इसके लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करना।
- समाज के कमजोर वर्गो अकुशल कामगारों को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना।
- कौशल विकास के माध्यम से नए कौशल सीखने तथा मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने का काम शामिल है जिसमें तकनीकी और व्यवहारिक कौशल भी सम्मिलित हैं।
- कौशल विकास के माध्यम से वैश्विक, घरेलू माँग और कार्यबल को संतुलित करना ।

साहित्यावलोकन

- आकाशदीप, पंवार, सीमा (2002) " राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास के अवसर", शोध मंथन, वो, XII, नः II अप्रैल–जून, पृष्ठ, 313–322,

इस शोध पत्र में मुख्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का वर्णन है। एन.ई.पी. 2020 में भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो इसकी परम्परा, संस्कृति मूल्यों, लोकाचार में परिवर्तन लाने तथा बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढने और विकसित होने के लिए समान अवसरों की सिफारिश करती है। विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उन्हें उनमें व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो सकें।

- कपूर, रवि शंकर (2024) "2025 में कौशल विकास को प्रोत्साहन जरूरी" (लक्ष्य असंभव नहीं), राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्मरण, 30 दिसम्बर, पृष्ठ।।

प्रस्तुत लेख के अनुसार भारत में विकास को बढ़ावा देने में साल 2024 में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका रही है। आईटी और अन्य तकनीकी कंपनियों ने रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए है। एक अनुमान के मुताबिक भारत वैश्विक क्षमता केन्द्रों का हब बनता जा रहा है। इन क्षमता केन्द्रो से साल 2025 में बेहतर की गुंजाइश है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार नई दिल्ली ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस नीति के प्रावधानों का चार भागों में विभाजन किया गया है। भाग – I स्कूल शिक्षा भाग– II उच्चतर शिक्षा, भाग– III अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे एवं भाग – IV क्रियान्वयन की रणनीति। इस प्रकार इन्ही भागों में कौशल विकास पर एन.ई.पी. 2020 में विस्तार से चर्चा की गई है।

कौशल विकास की आवश्यकता

21वीं सदी में दुनिया के कई देशों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी, कुशल कामगारों की वैश्विक व घरेलू माँग तथा भारत की युवा आबादी में ऐसी वजहें है जो कौशल विकास की जरूरत को दर्शाती है। युवा आबादी को उत्पादन से जोडने और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है। एक अनुमान के मुताबिक 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत

सबसे युवा देश है और 2050 तक इसकी कार्यशील आयु वाली आबादी में 13.3 करोड लोग और जुडने वाले है। इस युवा आबादी को कौशल विकास के माध्यम से कुशल कार्यबल में बदलने पर ही भारत एक बिकसित देश बन पायेगा।

कौशल विकास का अर्थ

कौशल विकास व्यक्ति के समग्र विकास का आधार हैं। यह शैक्षणिक उपलब्धियों से परे एक ऐसे व्यक्ति तैयार करता है जो आत्मविश्वास और सम्पूर्ण क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। अतः कौशल विकास से तात्पर्य योग्यताओं को हासिल करने, बढ़ाने और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु मौजूदा क्षमताओं को परिष्कृत करने की निरंतर प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को उनके व्यवहारिक और व्यावसायिक जीवन में प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है।

कौशल विकास के प्रमुख क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र, फर्नीचर और फिटिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी मोबाइल रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, मोटर वाहन, ब्यूटीशियन, हेल्थ केयर, योग, मशीन लर्निंग कौशल विकास प्रमुख क्षेत्र हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी नीतियों वे योजनाओं के माध्यम से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भविष्य मैं क्लाउड कम्प्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स, साइबर सुरक्षा, डाटा सांइम ऐसे क्षेत्र है जिनमें प्रशिक्षित युवाओं की माँग लगातार बढ़ेगी।

वर्तमान में कौशल विकास का महत्व

कौशल विकास एक व्यक्ति में आलोचनात्मक सोच व उसे समस्या समाधान करने में सक्षम बनाता है। कौशल विकास पर आधारित शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का समग्र विकास संभव है तथा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक है। जैसे–

- कौशल विकास के माध्यम से छात्र नई तकनीक और बदलते क्षेत्रो के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।
- कौशल विकास लोगों को अपनी नौकरी बनाए रखने में मदद करता है क्योकि कौशल विकास में निवेश करने वाले संगठन अपने कर्मचारियों को लम्बे समय तक बनाए रख सकतें है। जबकि भर्ती और प्रशिक्षण जैसी टर्न ओवर लागतों को कम कर सकते हैं।
- कौशल विकास के जरिये दक्षता हासिल करने से युवा कर्मचारियों तथा छात्रों को अधिक आत्मविश्वास मिलता है। जिससे उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नई परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती हैं।
- पेशेवर युवाओं के लिए आवश्यक दक्षता और कौशलों का विस्तार हो रहा है। प्रौधोगिकी में तेजी और वैश्विक बदलाबों के साथ सामजस्य बिठाने और अनुकूलन करने हेतु निरन्तर सीखने की जरूरत है जो कौशल विकास के माध्यम से पूरी हो सकती है।
- कौशल विकास के व्यक्ति के व्यक्तिगत व व्यवसायिक जीवन में अद्वितीय सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- किसी व्यक्ति के व्यवहारिक व व्यवसायिक जीवन में रुकावटों व जोखिमों को कम करने में कौशल विकास की भूमिका का काफी महत्व है।

भारत में कौशल विकास के अवसर

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (न्छथ्च्।) की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है। कि भारत की जनसंख्या का 77 वर्षो में दोगुना होने का अनुमान है। एक अनुमान के मुताबिक 144 करोड आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 24

प्रतिशत लोग 0–14 आयु वर्ग के, 17 प्रतिशत लोग 10–19 आयु वर्ग के, 26 प्रतिशत लोग 10–24 आयु वर्ग के थे। 68 प्रतिशत लोग 15–64 आयु वर्ग तथा 7 प्रतिशत लोग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। अर्थात भारत की अधिकांश आबादी युवा है दूसरी तरफ जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोपीय देशों में बुजुर्ग आबादी की अधिकता है। अतः भारत अपनी युवा आबादी को कुशल कार्यबल में तब्दील कर दें, तो यह उसके लिए वरदान साबित होगी। भारत को कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षन देकर वैश्विक और घरेलू मोर्चे पर अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।

–वर्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) की फ्यूचर ऑफ जाब्स रिपोर्ट 2025 के मुताविक 2030 तक काम के लिए जरूरी 40 प्रतिशत कौशल पूरी तरह बदल जायेंगे।

एआई (AI) और डाटा साइंस से जुड़े तकनीकी कौशल की माँग वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी साथ ही सृजनात्मक सोच, लचीलापन और पर्यावरण प्रबन्धन जैसे कौशलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों का भविष्य तेजी से बदल रहा है, जहाँ तकनीकी प्रगति की वजह से नौकारियों में गिरावट का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में व्यक्तिगत और तकनीकी कौशल का विकास ही इस बदलाव के साथ कदम मिलाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना तेजी से विकसित हो रहे रोजगार बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अपने युवाओं को प्रभावी ढंग से कौशल विकास पर टिका है। कौशल विकास के प्रयासों की सफलता देश के भविष्य को आकार देने और इसकी आर्थिक क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कौशल विकास हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतियाँ

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग, विश्वविध्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सहयोग से अपनी युवा आवादी को शिक्षित और प्रशिक्षित करने हेतु अनेक योजनाओं को शुरू किया है जो निम्न है–

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी. एम. के. वी. बाई)** – यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रभाणन योजना का मुख्य उद्देश्य भारी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योगों में शामिल होने में सक्षम बनाना और प्रोत्साहित करना है।
- **स्किल इंडिया मिशन** – यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार 2015 में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से शुरू किया था। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय युवाओ के बीच औद्योगिक और उधमशीलता कौशल का विकास करना, उद्योग की आवश्यकता व व्यक्ति के पास मौजूदा कौशल के बीच की खाई को पाटना है। यह भारत की पहली एकीकृत योजना है जिसमें समाज के सभी वर्गो को शामिल करने की पहल की गई है।
- **स्वंयम (swayam)** – स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइडस (swayam) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9 वीं + 12 वीं) से लेकर स्नातकोत्तर (पी, जी,) स्तर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और संचार प्रौधोगिकी के माध्यम से शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत, ऑनलाइन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
- **कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015** – भारत सरकार ने यह योजना जुलाई 2015 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार से जोडना जो कम पढ़े–लिखें है या बीच में स्कूल छोड देते हैं। इस योजना में एक करोड युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य 2020 तक पूरा किया जाना था।
- **जन शिक्षण संस्थान (जे. एस. एस)** – जन शिक्षण संस्थान भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित स्वायत्त संस्थान है इसे देशभर के गैर सरकारी संगठनों के

नेटवर्क के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य नव साक्षरों तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करना है।

- **प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र** – एम, एस, डी, ई, ने भारत के प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक आकांक्षात्मक मॉडल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की पहल की है। जिसमें सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो को शामिल किया जा सके। इन प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र नाम दिया गया है। यह कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मानकीकृत बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0** – केन्द्र सरकार इस योजना के तहत युवाओं को एआई, 3 डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने पर जोर दे रही है। देश में 30 स्किल इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर के साथ नेशनल अप्रेन्टिस शिप प्रमोशन स्कीम के जरिये युवाओं को बित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए सुविधाएं स्थापित की गई है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इसमें भारत की युवा आबादी को केन्द्र में रखते हुए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा मै लाने पर जोर दिया गया है। एन.ई.पी. 2020 का मकसद युवाओं को रोजगार और उद्यमिता लिए तैयार करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण में अकादमिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशलों को एकीकृत करने पर बल दिया गया है। इस नीति में कौशल विकास हेतु निम्न प्रावधान इस प्रकार है –
    - सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है ।
    - बुनियादी ढाँचे और आधुनिक प्रौधोगिकी से सुसज्जित और समर्पित व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना करना।
    - स्कूलों में कक्षा छः से व्यावसायिक शिक्षा शुरु करने और इंटर्नशिप की सिफारिश इस नीति में की गई है।
    - शिक्षण संस्थानों में इन्क्यूवेशन केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से विद्यार्थियो के बीच उधमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना नीति में शामिल है।

भारत में कौशल विकास की चुनौतियाँ

भारत में कौशल विकास मिशन के सामने कई चुनौतियाँ है जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन और प्रभाव में बाधा डालते हैं। इनमें से प्रमुख मुद्दे इस प्रकार है।

- **औद्योगिक कौशल की कमी** – सरकार का अनुमान था कि च्डड्ढटल के अन्तर्गत कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग स्वरोजगार की ओर मुडेंगें, इससे रोजगार सृजन में वृद्धि देखने को मिलेगी। परन्तु 24 प्रतिशत लोगों ने ही अपना स्वंय का व्यवसाय आरंभ किया तथा इनमें से भी सिर्फ 10 हजार लोगों में मुद्रा ऋण हेतु आवेदन किया यह चिंता की बात है।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता** – भारत एक विशाल युवा आबादी वाला देश है जिसे शिक्षित, प्रशिक्षिण करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता की जरूरत होगी। हमारे देश में प्रशिक्षण युक्त लोगों के मध्य रोजगार की दर बहुत ही कम है, इसकी मुख्य वजह पर्याप्त और गुणवत्ता परक प्रशिक्षण प्राप्त न होना रहा है। लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीखने की संभावनाएं सीमित होती है। जहाँ अभियांत्रिकी के छात्र किसी विषय में प्रशिक्षित होने में चार वर्ष का समय लेते है, वही उसी विषय के समरूप कोई कौशल विकास का प्रशिक्षण कुछ माह में प्राप्त किया जाना कठिन है।

- **विद्यार्थियों में आकर्षण की कमी** – कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे– पॉलिटेक्निक तथा आई. टी. आई. में इनकी क्षमता के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन कम होने की मुख्य वजह युवाओं के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरुकता व रूचि को माना जा सकता है।
- **उद्योग की सीमित भूमिका** – अधिकतर प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की सीमित भूमिका होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण उपरांत रोजगार तथा वेतन का स्तर निम्न बना रहा। उद्योगों का प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग व समन्वय के बिना कौशल विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है।
- **गतिशीलता और पहुँच** – दूर दराज और बंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- **वित्त पोषण और स्थिरता** – कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षण व मानव संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन की जरूरत होती है। इन योजनाओं की सफलता और निरंतरता के लिए स्थायी वित्त पोषण की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है।
- **बुनियादी ढाँचा और संसाधन** – भारत में कौशल विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन जनसंख्या के आकार को देखते हुए पर्याप्त नही है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित और सीमित कर सकते हैं।
- **नियोक्ता का रवैया** – भारत में बेरोजगारी में वृद्धि की समस्या के लिए कौशल प्रशिक्षण ही एक मात्र वजह नहीं है। उद्योगों व लघु उद्योगों का लोगों की नियुक्ति के प्रति अनिच्छा भी एक बड़ा कारण है।

निष्कर्ष

21 वीं सदी के भारत में एकीकृत और समावेशी विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक साधन कौशल विकास है। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में 'कौशल भारत–कुशल भारत' की सिद्धि बदलते समय की आवश्यकता बन चुकी है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत जैसी परिकल्पनाओं को साकार करने हेतु कौशल विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन समय की आवश्यकता है। भारत युवा आबादी बाला देश है। कौशल विकास रोजगार के अवसरों और रोजगार चाहने वालों के कौशल अन्तराल के बीच की खाई को पाटने बेरोजगारी दरों को कम करने और भारत की उभरती अर्थवस्था में कुशल कामगारों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

भारत को विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक माँग के अनुरूप युवाओं को कौशलयुक्त कार्यबल बनाने के लिए अवसरों का लाभ लेने की जरूरत हैं। विकासित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सरकारी सहायता, निजी क्षेत्र का सहयोग बेहतर प्रशिक्षण, बड़ी हुई जागरुकता, गुणवत्ता और परिणामों की नियमित समीक्षा को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कौशल विकास के द्वारा देश के सबसे बड़े वर्ग के रूप में युवाओं को उत्पाद और सशक्त बनाने का विजन, देश और समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020): ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 3–5 और 23–25,
2. आकाशदीप, पंवार, सीमा (2022) '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास के अवसर'' शोध मंथन, वो० 12, न–2, अप्रेल – जून, पृष्ठ 318–319,
3. शुक्ल, अरविन्द कुमार (2023) ''इक्कीसवीं सदी का भारत मुद्दे चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ'' (ई पुस्तक), आई जे ए आर एम एस पब्लिकेशन, कानपुर नगर (http//books.ijarms.org)

4. यू एन एफ पी ए (2023); ''बदलाव में बेहतर होता जीवन'' कम्युनिटी मैटर्स आउट लुक (विशेषांक), जून, 2023, पृष्ठ 8–11)

5. मंडल, अजित, दत्ता, इन्द्रजीत, प्रीतम, भानुप्रताप (संपादित) 2023: ''नेशनल ऐजूकेशन पॉलिसी रिफार्म एण्ड पर्सपक्टिब्ज,'' अटलान्टिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली,

6. कपूर, रविशंकर (2024): ''2025 में कौशल विकास को प्रोत्साहन –जरुरी'' राजस्थान प्रत्रिका, जयपुर संस्करण, 30 दिसम्बर, पृष्ठ 11,

बेवसाइट्स

1. http :// www.jagranjosh.com
2. https: //epaper.patrika.com
3. www. drishtiias.com
4. http: // www. nextias.com
5. http: // www.amarujala.com
6. http: // vajiramand ravi.com

❖◆❖